नईदुनिया

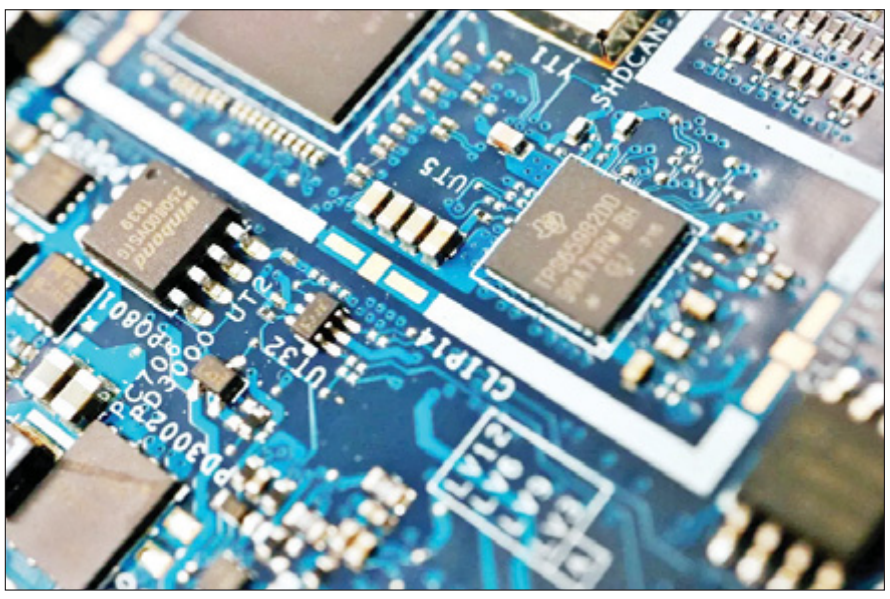

भारत बनेगा सेमीकंडक्टर हब! 2027 तक कंपनियां 31,299 करोड़ का निवेश करेंगी

नई दिल्ली

भारत के महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) को गति मिल रही है। इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ताजा अनुमानों के मुताबिक आईएसएम के तहत पात्र सेमीकंडक्टर कंपनियां वित्त वर्ष 2027 तक संयुक्त रूप से 31,299 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी।

माइक्रोन और काइन्स ने शुरू किया उत्पादन, टाटा और सीजी पावर की परियोजनाएं भी प्रगति पर

यह 1,64,291 करोड़ रुपये के कुल प्रतिबद्ध निवेश का लगभग 20 प्रतिशत है, जो देश में चिप निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 तक पांच सेमीकंडक्टर कंपनियों ने अपनी परियोजनाओं में 15,799 करोड़ रुपये का निवेश किया था।

अगले 12 महीनों में, यानी 31 मार्च 2027 तक, 15,500 करोड़ रुपये का और निवेश आने की उम्मीद है। 2023 में शुरू हुई यह योजना वास्तव में वित्त वर्ष 2025 में तब तेजी पकड़ी जब माइक्रोन को मंजूरी मिली और उसने गुजरात के साणंद में अपने एटीएमपी संयंत्र में निवेश शुरू किया।

इस योजना के तहत, सरकार परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक प्रोत्साहन देती है, साथ ही राज्य सरकारें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त योगदान करती हैं। माइक्रोन और काइन्स सेमीकान ने पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

सीजी पावर से जुलाई में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है, जबकि टाटा के असम स्थित ओएसएटी संयंत्र से इस साल के अंत तक वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की संभावना है। टाटा की गुजरात के धोलेरा में फैब संयंत्र परियोजना सबसे बड़ी है, जिसमें 91,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है और 2028 तक इसके तैयार होने की उम्मीद है। यह आईएसएम के तहत कुल निवेश का 55 प्रतिशत है।

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, सेमीकंडक्टर संयंत्र की लागत में 65 प्रतिशत हिस्सा मशीनों का होता है, इसलिए आने वाले वर्षों में उपकरणों की खरीद और स्थापना में बड़ा निवेश देखने को मिलेगा।

आईएसएम योजना के तहत अब तक 76,000 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोत्साहन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें देश भर में दो फैब परियोजनाएं और 10 ओएसएटी संयंत्र शामिल हैं। सरकार निवेश की नियमित समीक्षा कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, जिससे भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकेगा।

न्यूज ब्रीफ

अमेरिकी आदेश के बाद एन्थ्रोपिक ने बंद किए अपने सबसे एडवांस एआई माडल

नई दिल्ली। अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एन्थ्रोपिक ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अमेरिकी सरकार के आदेश के बाद अपने सबसे उन्नत एआई माडल फेविल 5 और मायथास 5 को सभी विदेशी उपयोगकर्ताओं के लिए बंद कर दिया है। एन्थ्रोपिक को मिले निर्देश में फेविल 5 के सुरक्षा उपायों को बायपास या जेलब्रेक करने की आशंका जताई गई है, जिससे साफ्टवेयर कमजोरियों का पता लग सकता है। हालांकि, कंपनी ने केवल एक संभावित सीमित जेलब्रेक के मौखिक सबूत मिलने की बात कही। एन्थ्रोपिक ने करोड़ों लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कमर्शियल माडल को ऐसे सीमित कारण से वापस लेने को अनुचित बताया है, जिससे एआई डेवलपर्स और नियामकों के बीच तनाव बढ़ा है। यह कार्रवाई कंपनी के ट्रंप प्रशासन से पुराने विवाद और अमेरिकी सेना को अपने एआई माडल घरेलू निगरानी या स्वचालित हथियारों के लिए देने से इनकार के बाद हुई है, जिसके जवाब में सरकार ने उसे ब्लैकलिस्ट किया था। यह घटना विदेशी एआई क्षमताओं को रोकने के अमेरिकी प्रयासों में एक बड़ा बदलाव भी दर्शाती है, जहां अब निर्यात नियंत्रण का ध्यान एआई तक विदेशी पहुंच को सीधे सीमित करने पर है, जो पहले चिप्स और टूल्स पर केंद्रित था। एन्थ्रोपिक ने इस सरकारी कार्रवाई को निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित नियमन के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं बताया है।

रुपया में सप्ताहिक तौर पर डालर के मुकाबले मामूली कमजोरी रही

नई दिल्ली। पिछले सप्ताह भारतीय रुपये का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा। डालर के मुकाबले रुपये में सप्ताह भर में 0.18 फीसदी की मामूली गिरावट दर्ज की गई, हालांकि सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन इसमें अच्छी मजबूती देखने को मिली, जिससे हुई कुल साप्ताहिक गिरावट में कुछ सुधार आया। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन रुपया डालर के मुकाबले 0.68 फीसदी की तेजी के साथ 95.11 प्रति डालर पर बंद हुआ। यह गुरुवार के 95.76 प्रति डालर के मुकाबले एक महत्वपूर्ण सुधार था, जब रुपये में उल्लेखनीय कमजोरी देखी गई थी। दिन के कारोबार के दौरान रुपया 94.94 के स्तर तक भी पहुंचा था, जो बाजार के बेहतर माहौल को दर्शाता है। रुपये में आई इस मजबूती की मुख्य वजह पश्चिम एशिया में युद्ध थमने की उम्मीद के बीच कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, बाजार का बेहतर होता माहौल और अमेरिका-ईरान के बीच कूटनीतिक सफलता की संभावनाओं से डालर का कमजोर होना रहा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के विदेशी मुद्रा विनियम के शोध विश्लेषक दिलीप परमार ने इस बात पर जोर दिया कि रुपये ने गुरुवार को हुए नुकसान की काफी हद तक भरपाई की है। रुपया फिलीपींस के पेसो, दक्षिण कोरियाई वान और इंडोनेशियाई रुपिया के बाद एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में से एक रहा। हालांकि, फरवरी के अंत में पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से डालर के मुकाबले रुपये में कुल 4.35 फीसदी की गिरावट आ चुकी है, जो लंबी अवधि की चुनौतियों को दर्शाता है।

मई में ट्राइबर की 1,890 यूनिट्स बिकीं, बनी नंबर-1

नई दिल्ली। बीते मई महीने रेनो ट्राइबर एक बार फिर कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है।

मई में ट्राइबर की 1,890 यूनिट्स बिकीं, जबकि मार्च में पोर्टफोलियो में शामिल हुई नई डस्टर की बिक्री में बड़ी गिरावट दर्ज की गई और वह 1,267 यूनिट्स पर सिमट गई। रेनो इंडिया की मई 2026 की बिक्री के आंकड़े सामने आ गए हैं। यह आंकड़ा कंपनी के लिए अप्रत्याशित है, क्योंकि अप्रैल में डस्टर ने 2,359 यूनिट्स के साथ रेनो की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का स्थान हासिल किया था। मई में काइगर की 656 यूनिट्स और क्विड की 300 यूनिट्स बिकीं, जिससे अप्रैल में 5,413 यूनिट्स की तुलना में रेनो की कुल बिक्री मई में 4,113 यूनिट्स पर गिर गई। रेनो ट्राइबर अपनी 7-सीटर क्षमता, किफायती मूल्य (शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपए) और सुरक्षा सुविधाओं के कारण ग्राहकों के बीच लगातार लोकप्रिय बनी हुई है। इसके टाप वेरिएंट में इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, 8 इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7 इंच का टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्ट एक्सेस कार्ड और वायरलेस स्मार्टफोन रेप्लिकेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। ट्राइबर में 1.0-लीटर, नैचुरली एस्पिरेटेड, 3-सिलेंडर इंजन लगा है जो 72 पीएस की पावर देता है और यह 5-स्पीड मैनुअल और एएमटी दोनों विकल्पों के साथ उपलब्ध है। डीलर स्तर पर सीएनजी किट का विकल्प भी मौजूद है।

अशोक लीलैंड का डिफेंस में नया दौर : ड्रोन आटोनोमस और 11,000 करोड़ का दांव

विदेशी बाजारों में अपनी उपस्थिति को मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य

नई दिल्ली

भारत की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन निर्माता और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बस कंपनी अशोक लीलैंड अपने डिफेंस मोबिलिटी कारोबार में एक महत्वपूर्ण बदलाव और विस्तार के लिए कमर कस रही है। कंपनी आगामी वर्षों में लाजिस्टिक्स ड्रोन, आटोनामस वाहनों और हाइड्रोजन-फ्यूल तकनीक जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में प्रवेश के साथ एक नया अध्याय शुरू करने की तैयारी में है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अशोक लीलैंड अगले तीन से पांच वर्षों में भारत के 11,000 करोड़ रुपये के डिफेंस मोबिलिटी टेंडरों पर बड़ा दांव लगाने के साथ-साथ विदेशी बाजारों में अपनी उपस्थिति को मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। कंपनी की डिफेंस टीम कई नए विकल्पों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, जो भविष्य की युद्धभूमि की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। इनमें सबसे प्रमुख अपने प्रतिष्ठित डिफेंस ब्रांड स्टैलियन का आटोनामस वर्सन विकसित करना है। अशोक लीलैंड के रक्षा व्यवसाय के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय सशस्त्र बलों के मुख्य वाहन स्टेलियन को आटोनामस बनाना एक चुनौती है, और हम इस पर काम कर रहे हैं। यह भविष्य का कार्यक्रम है जिसमें कनेक्टेड वाहन शामिल होंगे। इन स्व-चालित वाहनों का उपयोग लाजिस्टिक्स आपूर्ति और कुछ महत्वपूर्ण अग्रिम सैन्य आपरेशनों में होने की संभावना है, जिससे सैनिकों की सुरक्षा और दक्षता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर (वीएफजे) के साथ मिलकर हाइड्रोजन-फ्यूल पर चलने वाले स्टैलियन पर भी काम कर रही है, जो स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कंपनी रक्षा उद्देश्यों के लिए लाजिस्टिक्स ड्रोन क्षेत्र में संभावित प्रवेश की भी संभावनाएं तलाश रही है, जो सैन्य आपूर्ति और निगरानी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। कंपनी का लक्ष्य विदेशी कारोबार बढ़ाना: घरेलू बाजार के साथ-साथ, अशोक लीलैंड विदेशी बाजारों पर भी बड़ा दांव लगा रही है। कंपनी का लक्ष्य विदेशी कारोबार से राजस्व को मौजूदा लगभग 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना है। इस विस्तार की रणनीति के तहत, अशोक लीलैंड ने हाल ही में इंडोनेशिया की प्रमुख सरकारी रक्षा एवं औद्योगिक उपकरण निर्माता कंपनी पीटी पिंडाड के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। यह सहयोग इंडोनेशिया में इलेक्ट्रिक बसों (ईवी) और रक्षा वाहनों के संयुक्त विकास और निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान करेगा। कंपनी मुख्य रूप से सार्क देशों, अफ्रीका और आसियान पर ध्यान केंद्रित कर रही है, साथ ही खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देशों को भी लक्षित कर रही है। यूएई में पहले से ही एक संयंत्र होने के कारण, अशोक लीलैंड खाड़ी क्षेत्र में एक और प्लांट लगाने पर विचार कर रही है, जो उसके वैश्विक विनिर्माण पदचिह्न को मजबूत करेगा। लगभग 2,000 करोड़ रुपये के आर्डर: अशोक लीलैंड के पास वर्तमान में रक्षा क्षेत्र में लगभग 2,000 करोड़ रुपये के आर्डर हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत घरेलू हैं। कंपनी के पास भारतीय सशस्त्र बलों को सेवा देने वाले लगभग 30 प्लेटफार्म हैं, जिनमें से अधिकांश आयातित वाहनों को बदल रहे हैं या नए वाहन अनुप्रयोगों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

बान्ड बाजार में लौटी रौनक कंपनियों व संस्थानों ने जुटाए 27,000 करोड़

नई दिल्ली

इस हफ्ते भारतीय कारपोरेट बान्ड बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई, जहां कंपनियों और संस्थानों ने करीब 27,000 करोड़ रुपये जुटाए। बान्ड यील्ड में आई गिरावट के कारण उधार लेने की लागत कम होने से कंपनियों ने बड़े पैमाने पर बान्ड जारी करना शुरू कर दिया है। यह तेजी प्रारंभिक वित्त वर्ष में देखी गई सुस्ती के बाद आई है, जब ऊंची यील्ड ने उधारकर्ताओं को बैंक ऋण का सहारा लेने पर मजबूर किया था। इस सप्ताह अच्छी रेटिंग वाले कारपोरेट बान्ड पर यील्ड लगभग 50 से 70 आधार अंक तक कम हुई, जबकि 10 साल के सरकारी बान्ड पर यील्ड में करीब 9 आधार अंक की गिरावट दर्ज की गई। यील्ड में इस अनुकूल कमी ने कंपनियों के लिए बान्ड बाजार से पूंजी जुटाना अधिक आकर्षक बना दिया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के हालिया नीतिगत समर्थन और पूंजी जुटाने के लिए उठाए गए कदमों, जैसे विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक (बी) जमा और बाह्य वाणिज्यिक उधारी को बढ़ावा देने से भी पूंजी जुटाने की स्थिति में सुधार हुआ है और रुपये को स्थिर करने में मदद मिली है। बाजार में यह उत्साह अगले हफ्ते भी जारी रहने की उम्मीद है। हाउसिंग ऐंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन (हडको), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान अगले हफ्ते बान्ड से कुल 13,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहे हैं।

अगले हफ्ते भी जारी रहेगा बान्ड जारी करने का सिलसिला

चालू वित्त वर्ष के शुरुआती दो महीनों (अप्रैल और मई) में प्राथमिक बाजारों में काफी कम गतिविधियां देखी गई थीं, जब भारतीय कंपनियों ने घरेलू बान्ड बाजार से केवल 1.07 लाख करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई थी। यह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले लगभग 58 फीसदी कम थी और वित्त वर्ष 2023 के बाद से किसी भी वित्त वर्ष के शुरुआती दो महीनों में जुटाई गई सबसे कम रकम थी। इस सप्ताह नेशनल बैंक फार फाइनैंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड डेवलपमेंट (नैबफिड) ने गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के जरिये 5,000 करोड़ रुपये जुटाए।

केंद्र सरकार बना रही बीएस7 उत्सर्जन मानदंडों को लागू करने की योजना

नई दिल्ली। साल 2030 तक केंद्र सरकार भारत स्टेज सातवें (बीएस7) उत्सर्जन मानदंडों को लागू करने की योजना बना रही है, जिसके लिए चालू वित्त वर्ष में अधिसूचना जारी की जा सकती है। यह कदम देश में आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने और भारत स्टेज छठवें (बीएस6) मानदंडों को उन्नत करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है, जिन्हें आखिरी बार 2020 में लागू किया गया था। प्रस्तावित बीएस7 नियम यूरोपीय संघ के यूरो 7 मानकों के अनुरूप होंगे, लेकिन इन्हें भारतीय सड़क की स्थिति और ईंधन की गुणवत्ता के लिए अनुकूलित किया जाएगा। इन नए मानदंडों में सख्त उत्सर्जन सीमाएं निर्धारित करने और वास्तविक दुनिया में उत्सर्जन की निगरानी, आनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स तथा वाहन स्थायित्व के लिए आवश्यकताओं को पेश करने की उम्मीद है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अंतर-मंत्रालयी चर्चा शुरू कर दी है, साथ ही आटोमोबाइल निर्माताओं, ईंधन खुदरा विक्रेताओं और परीक्षण एजेंसियों से परामर्श भी किया जा रहा है। उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि नए बीएस7 मानदंडों को अपनाने से प्रति वाहन निर्माण लागत 30,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक बढ़ सकती है, जो सीधे ग्राहकों के लिए वाहनों की कीमतों में वृद्धि के रूप में परिलक्षित होगी।

रिलायंस अनिल अंबानी समूह के दो पूर्व अधिकारियों को ईडी ने किया गिरफ्तार

पीएमएलए के तहत हुई गिरफ्तारी, बैंक लोन धोखाधड़ी की जांच जारी

मुंबई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह पर अपना शिकंजा कसते हुए प्रिवेंशन आफ मनी लान्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दो पूर्व अधिकारियों सतीश सेठ और गौतम दोषी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई कथित बैंक लोन फ्राड से संबंधित सीबीआई की जांच के बाद हुई है। इसी के साथ नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिससे समूह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

सेठ और दोषी रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड के पूर्व निदेशक रह चुके हैं। उन पर भारतीय स्टेट बैंक को 114.98 करोड़ रुपए के कथित लोन फ्राड का आरोप है, जिसके संबंध में सीबीआई ने पहले मामला दर्ज किया था। ईडी ने सीबीआई की इसी शिकायत का संज्ञान लिया है। उन्हें आगे की कस्टडी के लिए दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा। एसबीआई उन 11 बैंकों के कंसोर्टियम का हिस्सा था, जिन्होंने रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड को कुल 735 करोड़ रुपए की टर्म लोन सुविधा मंजूर की थी। दूसरी ओर एनसीएलटी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस इन्फ्राटेल लिमिटेड को दिए गए ऋणों के लिए व्यक्तिगत गारंटर के रूप में अनिल अंबानी की भूमिका को लेकर एसबीआई की याचिका मंजूर कर ली है। अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने इस फैसले को कानूनी रूप से चुनौती देने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि जून में सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के पूर्व ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ झुनझुनवाला को भी इसी तरह के एक बड़े लोन फ्राड के आरोप में गिरफ्तार किया था।

पूंजीगत व्यय में राज्यों का निराशाजनक प्रदर्शन, अप्रैल में सिर्फ 1.85 फीसदी का उपयोग

22 राज्यों का संयुक्त बजट अनुमान 10.61 लाख करोड़ था, खर्च हुए केवल 19,604 करोड़

नई दिल्ली

वित्त वर्ष 2026-27 के पहले महीने अप्रैल में देश के 22 राज्यों ने अपने संयुक्त वार्षिक बजट के अनुमानित पूंजीगत व्यय का बेहद कम हिस्सा ही उपयोग किया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के मासिक खातों के विश्लेषण से पता चला है कि इन राज्यों ने 10.61 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित पूंजीगत व्यय का केवल 19,604 करोड़ रुपये ही खर्च किया। यह न केवल पिछले वर्ष अप्रैल के 2.26 प्रतिशत (21,981 करोड़ रुपये) की तुलना में कम है, बल्कि बजट में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद वास्तविक खर्च में 11 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है, जो राज्यों में विकास कार्यों की धीमी गति का संकेत है। विश्लेषण के अनुसार पिछले वित्त वर्ष के इसी महीने की तुलना में पूंजीगत व्यय कम खर्च हुआ है। इन्हीं राज्यों के समूह ने वित्त वर्ष 26 में तत्कालीन बजट अनुमान 9.71 लाख करोड़ रुपये में से 21,981 करोड़ रुपये (2.26 प्रतिशत) खर्च किया था। हालांकि वित्त वर्ष 27 में पूंजीगत व्यय के बजट अनुमान में करीब 9.3 प्रतिशत की वृद्धि की गई, लेकिन पहले महीने का वास्तविक खर्च 11 प्रतिशत कम हो गया। राज्यों की अलग-अलग बात करें तो केरल ने पहले महीने में सालाना बजट का करीब 22.31 प्रतिशत खर्च कर शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसके बाद हरियाणा (12.92 प्रतिशत) रहा। इस क्रम में राजस्थान (5.16 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (4.24 प्रतिशत), तेलंगाना (4.17 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (3.71 प्रतिशत) ने भी शीर्ष सूची में जगह बनाई। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक अनुमानित पूंजीगत व्यय 1.94 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, लेकिन इस राज्य ने अप्रैल में मात्र 0.01 प्रतिशत ही खर्च किया।

पूंजीगत व्यय के कम व्यय के मामले में उत्तराखंड (0.18 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (0.23 प्रतिशत), मेघालय (0.27 प्रतिशत), त्रिपुरा (0.05 प्रतिशत) और बिहार (0.50 प्रतिशत) जैसे राज्यों ने भी निराशाजनक प्रदर्शन किया। तीन राज्यों - महाराष्ट्र (-0.74 प्रतिशत), ओडिशा (-0.41 प्रतिशत) और झारखंड (-0.02 प्रतिशत) - ने अप्रैल में शुद्ध नकारात्मक पूंजीगत व्यय दर्ज किया, जिसका अर्थ है कि नए खर्च की तुलना में प्राप्तियां अधिक थीं। नियंत्रक सामान्य लेखा के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 27 के पहले महीने में अपने पूंजीगत व्यय के लक्ष्य का 15.5 प्रतिशत खर्च किया, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में यह 14.3 प्रतिशत था, जिससे राज्यों की सुस्ती और अधिक स्पष्ट होती है। हालांकि, राजस्व व्यय अपेक्षाकृत स्वस्थ गति से बढ़ा।